



मास्क जरूरी,
नहीं कोई मजबूरी

सुविचार
अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें! किस्मत की आजमाईश तो जुए में होती है..

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-3 • 29 JULY TO 04 AUGUST 2021 • VOLUME-2 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

✓ STUDY ✓ WORK ✓ SETTLE IN ABOARD

Low Filing Charges & *Pay Money after the visa

IELTS • STUDY ABROAD

CANADA AUSTRALIA USA

U.K SINGAPORE EUROPE

T&C apply

मुख्यमंत्री ने पीएसपीसीएल को सभी एकतरफा खरीद समझौते रद्द करने को कहा

बिजली की चरम मांग के समय खरा न उतरने का लिया गंभीर नोटिस

• चंडीगढ़, ब्यूरो



मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को उन प्राइवेट कंपनियों के साथ किये एकतरफा सभी बिजली खरीद समझौते (पीपीएज़) रद्द करने या फिर से देखने के लिए कहा है, जो कंपनियों के धान की बिजली और गर्मी के सीजन में बिजली की चरम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सप्लाई देने के लिए किये गए समझौते पर खरा नहीं उतरती। तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मानसा जो राज्य के सबसे बड़े निजी थर्मल प्लांटों में से एक है, की धान के मौजूदा सीजन दौरान बड़ी असफलता का गंभीर नोटिस लेते हुए मुख्यमंत्री ने पीएसपीसीएल को इसके

पीपीए रद्द करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि यह समझौता कंपनी के हक में बहुत ज्यादा जाता है। उन्होंने पीएसपीसीएल को यह भी कहा कि पिछली अकाली-भाजपा सरकार द्वारा विभिन्न स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपीज़) जो मूलभूत तौर पर राज्य की खासकर धान की बिजली और गर्मी के मौसम दौरान पैदा होती मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किये गए थे, के साथ किये गए सभी बिजली खरीद समझौतों की जांच की जाये। उन्होंने पीएसपीसीएल को निर्देश दिए कि सभी एकतरफा पीपीएज़ रद्द करें/फिर से जाँच की जाए जिनका राज्य को कोई फायदा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएसपीसीएल ने साल 2007 के बाद थर्मल/हाईड्रो के साथ 12 बिजली खरीद समझौते और सोलर/बायोमास के साथ लंबे समय के 122 समझौते किये थे जिससे राज्य की बिजली पैदावार सामर्थ्य को लगभग 13800 मेगावाट करके पंजाब को अतिरिक्त बिजली वाला राज्य बनाया जाये। हालांकि धान के सीजन के दौरान तलवंडी साबो थर्मल प्लांट के सभी तीनों ही यूनिट बिजली की मांग के शिखर के दौरान कुछ दिनों के लिए

बिजली पैदा करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड की एक यूनिट मार्च 2021 से नहीं चल सकी और दो यूनिट पिछले एक महीने से बिजली पैदा करने से असमर्थ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय तलवंडी साबो पावर लिमिटेड का सिर्फ एक यूनिट चल रहा है और इन कारणों से राज्य में बिजली की भारी कमी आई है। पीएसपीसीएल ने पहले ही तलवंडी साबो पावर लिमिटेड को जुर्माना लगा कर नोटिस जारी कर दिया है परन्तु क्योंकि बिजली खरीद समझौते (पीपीए) एकतरफा हैं, इसलिए लगाया गया जुर्माना थर्मल प्लांटों में खराबी होने के कारण हुए नुकसान के मुकाबले बहुत थोड़ा होगा।

प्रधानमंत्री आज देश के शिक्षण समुदाय को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सुधारों के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 29 जुलाई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा देशभर के शिक्षा व कौशल विकास के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, छात्रों, शिक्षकों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ करेंगे जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास का विकल्प प्रदान करेगा।



केंद्रीय मंत्रीमंडल ने डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन को दी मंजूरी

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य किसी संकट के कारण बैंक पर लेन-देन को पाबंदी लागू होने की स्थिति में उसके जमाकर्ताओं को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए 90 दिन के भीतर उन्हें पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि प्राप्त करने का अवसर सुनिश्चित करना है। पिछले साल सरकार ने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक जैसे संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को सहायता देने के लिए जमा राशि पर बीमा आवरण को पांच



गुना बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था। पीएमसी बैंक के डूबने के बाद यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक भी संकट आए, जिनका पुनर्गठन नियामक और सरकार द्वारा किया गया। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 में संशोधन की घोषणा

वित्त मंत्री ने आम बजट में की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इस विधेयक को मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। विधेयक के कानून बनने के बाद इससे उन हजारों जमाकर्ताओं को तत्काल राहत मिलेगी, जिन्होंने अपना धन पीएमसी बैंक और दूसरे छोटे सहकारी बैंकों में जमा किया था। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा तब लागू होता है, जब किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और परिसमापन प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, सिंधु नदी का जलस्तर बढ़ा

जम्मू. जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है। बुधवार को अमरनाथ गुफा के पास अचानक बादल फटने से सिंधु नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई है। हालांकि, यहां दो एसडीआरएफ टीमों पहले से मौजूद हैं। अमरनाथ यात्रा इस बार स्थगित है और जिस स्थान पर ये हादसा हुआ है, वहां अभी कोई भी यात्री मौजूद नहीं है। इससे पहले किश्तवाड़ जिले के



एक सुदूर गांव में तड़के साढ़े चार बजे बादल फटने से सात लोगों की मौत हो गई थी और 17 अन्य घायल हुए थे। इसके साथ ही कई मकानों, खड़ी फसलों

और एक लघु पनबिजली संयंत्र को नुकसान पहुंचा था। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अधिकारी स्थितियों को लेकर सतर्क हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित

शाह ने इस बारे में जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से बात कर जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि राहत कार्यों व स्थिति के सटीक आकलन के लिए एनडीआरएफ की टीमों वहां भेजी जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल के विभिन्न क्षेत्रों में दो बादल फटने से एक लघु पनबिजली परियोजना, लगभग 12 मकान और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है।

पहले विधायक कहते थे हम गांव में कैसे जाएंगे अब शहर में पार्श्वों को ये डर सताने लगा है

राजनीति में नया स्टंट! पहले 4 साल कुछ न करो...आखिर के साल में विकास कार्यों के नाम पर शहर उखाड़ दो



• **संभल कर चले** : जगह-जगह सड़कों का यही हाल है। जहां मुसाफिरों को दिक्कत हो रही है वहीं दुर्घटनाओं का भी खतरा है।

फोटो : रवि

• **जालंधर ब्रीज**. विशेष रिपोर्टर

जहां संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों द्वारा केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करके लोक सभा और राज्य सभा को नहीं चलने दिया जा रहा है जिसमें उनके द्वारा मुख्य मुद्दे तीनों कृषि बिलों को रद्द करवाने की मांग और पंगासस सॉफ्टवेयर द्वारा की जा रही जासूसी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है।

लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, बावजूद सत्तापक्ष के ही पार्श्वों और विधायकों द्वारा अपनी ही पार्टी के किए जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। पंजाब में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है लेकिन कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी सर्रास सामने



नगर निगम जालंधर

आ रही है और उसको रोकने के लिए दिल्ली हाई कमान द्वारा काफी कोशिशें की जा रही हैं। पिछले कुछ महीनों से सत्तापक्ष के विधायकों को लगने लगा है कि वह किस रिपोर्ट कार्ड को लेकर गांव में लोगों से वोट मांगने जाएंगे। क्योंकि उनके द्वारा इलेक्शन से पहले किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इसी तरह जालंधर शहर में भी पार्श्वों को लगने लगा है कि नगर निगम में बैठे अफसरों द्वारा उनके कोई काम नहीं किए जा रहे हैं और लोगों द्वारा उनको पार्श्व बनाया गया है। परन्तु दो दिन पहले हुई हाउस की मीटिंग में भी अफसरों द्वारा मीटिंग का बॉयकट किया गया और पार्श्वों द्वारा मेयर और कमिश्नर समक्ष आवाज उठाई गई। अगर अफसरों द्वारा ऐसे ही उन्हें



• **निगम हाउस में मेयर और कमिश्नर को घेरे सत्तापक्ष और विपक्ष के पार्श्व**

अपमानित किया जाना है तो मीटिंग क्यों बुलाई जाती है। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कुछ शहरों

को चुना गया था जिसमें जालंधर शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा फंड दिए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष और सत्तापक्ष के पार्श्वों द्वारा स्मार्ट सिटी के फंड का दुरुपयोग को लेकर हाउस की मीटिंग में जमकर हंगामा किया गया और स्मार्ट सिटी के कार्य को घटिया तरीके से कराया जा रहा है और उन सब कार्यों को चेक करने के लिए निगम के पास कोई स्टाफ उपलब्ध नहीं है। जिक्रयोग्य है कि स्मार्ट सिटी कार्य को छोड़ बाकी पूरे शहर में हल्की सी बारिश होने पर गंदे पानी की समस्या, सीवरेज जाम टूटी सड़कें और जगह-जगह कूड़े के ढंप हर एक वार्ड के पार्श्वों द्वारा मुख्य समस्या बताई गई है।

बता दें नगर निगम जालंधर इस वक्त कॉन्स्ट्रक्टर पर रखे मुलाजिमों पर ही निर्भर है और पक्के न होने के कारण वह लोगों और पार्श्वों की परवाह भी नहीं करते जिससे

आने वाले 6 महीने सत्तापक्ष पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। गौरतलब है कि जबसे नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रधान बनाया गया है पार्टी के वर्कर समझ नहीं पा रहे हैं कि वह अपनी समस्याओं को लेकर किधर जाएं, पार्टी प्रधान या मुख्यमंत्री कार्यालय। एक बड़ी समस्या यह भी देखने को मिल रही है पार्टीयों की आपसी मतभेद, गुटबाजी के बीच जिन अधिकारियों पर शहर को स्मार्ट व समस्याओं को निपटारे की जिम्मेवारी है वे पीस कर रह गए हैं जिस कारण अगर कोई अधिकारी जनता के हित में कोई कार्य करना भी चाहे तो वह नहीं कर पा रहा है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आने के लिए गांवों में विधायकों और शहरों में पार्श्वों के मुद्दों को हल करवा पाएगी या सिर्फ अंदरूनी झगड़ों में ही अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी।

